बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 198 ● नई दिल्ली ● वीरवार 07 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

### अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को वाईवासा कोर्ट से जमानत मिली

नई दिल्ली झारखंड के चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी। राहुल गांधी के अदालत में पेशी के लिए आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने चाईबासा में सुरक्षा बढ़ा दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। अधिकारियों के अनुसार, राहुल गांधी रांची से हेलीकॉप्टर द्वारा चाईबासा पहुँचे। उनके लिए टाटा कॉलेज मैदान में एक हेलीपैड बनाया गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता मंगलवार को झारखंड के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा पहुंचे।

# बीजेपी ने आप पर लगाया 650 करोड़ के घोटाले का आरोप; कहा- बीजेपी हॉस्पिटल के निर्माण में साजिशन किया बार-बार बदलाव

नई दिल्ली। कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत से राहत मिलने के एक दिन बाद ही पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एक अन्य विवाद में सामने आ गए हैं। दिल्ली सरकार ने लोकनायक अस्पताल के 22 मंजिला नए ब्लाक के बनाए जाने में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच के लिए फाइल एलजी वी के सक्सेना के पास भेज दी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि लोकनायक अस्पताल में जिस इमारत का अनुबंध 465 करोड़ का किया गया था, एक साजिश के तहत बार-बार बदलाव कर इसकी लागत बढ़कर 1139 करोड़ तक पहुंचा दी गई। इस मामले में एक साल पहले उपराज्यपाल द्वारा गठित की गई समिति ने सवाल उठाए हैं। समिति ने कई अन्य तरह के भी आरोप लगाए गए हैं। जिसकी रिपोर्ट आने पर दिल्ली सरकार ने अब फाइल भेज कर एलजी से इस मामले में सीबीआई से जांच की सिफारिश की है। आरोपों पर आप ने प्रतिक्रिया देते हुआ है कि भाजपा और उसके मंत्री एसीबी, सीबीआई और ईडी के चक्कर में पड़े हैं। वे हर दिन आप नेताओं के खिलाफ साजिश रचते हैं, बेबुनियाद और झूठे मामले तैयार करने में समय बर्बाद करते हैं और इन दिशाहीन जांचों पर करदाताओं का पैसा बर्बाद करते हैं। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह एक बड़ा घोटाला है जो बहुत सफाई के साथ किया गया है, जांच होने पर आरोपी बच नहीं

पाएंगे। वर्मा ने कहा है कि पूर्व लोक निर्माण मंत्री जैन ने नियमों को दरकिनार कर इसमें बदलाव करवाए। वह निरीक्षण करने जाते थे और किसी मंशा के तहत बदलाव सुझाते थे जिससे लागत बढ़ जाती थी। 650 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। बता दें कि इमारत के निर्माण में अतियमितताओं की बात सामने आने पर पिछले साल उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा प्रक्रियात्मक खामियों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने पाया है कि मूल अनुबंध राशि 465 करोड़ रुपये थी, जो लगभग 243 प्रतिशत बढ़कर 1,139 करोड़ रुपये हो गई है। पसंदीदा वास्तुकार सलाहकार का चयन एक संदिग्ध प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जिसमें अनियमितताएं बरती गईं और सामान्य वित्तीय विनियमन (जीएफआर) के प्रविधानों का घोर उल्लंघन किया गया। बिना किसी निविदा के नामांकन के आधार पर मेसर्स सिक्का एसोसिएट्स को 5.27 करोड़ रुपये मूल्य के 84,420 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए परामर्श कार्य दिया गया 6 सलाहकारों को सूचीबद्ध करते समय यह विशेष रूप से ध्यान में रखा गया था कि प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से वित्तीय बोली आमंत्रित की जाएगी, हालांकि इस शर्त का उल्लंघन किया गया और फिर जिलावार या क्षेत्रवार सलाहकारों की नियुक्ति का मनमाना निर्णय लिया गया। जिला केंद्रीय से संबंधित परामर्श कार्य के लिए 5.62 करोड़ रुपये मूल्य के 90,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं। परामर्शदाता को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए, क्षेत्र को गुप्त रूप से बढ़ाकर 1,62,490 वर्ग मीटर कर दिया गया, जिससे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के निर्णय के अनुसार देय परामर्श शुल्क 5.62 करोड़ रुपये से बढ़कर 10.15 करोड़ रुपये हो गया।

## मोबाइल के दौर में किताबें पढ़ने का अपना ही चाव..., दिल्ली पुस्तक मेले में बोलीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मोबाइल के इस दौर में भी किताबें पढ़ने का अपना ही चाव है। किताबों का विकल्प ई-गैजेट्स कभी नहीं हो सकते। पूर्व में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की अध्यक्ष भी रह चुकीं रेखा ने कहा कि प्रेमचंद सहित देशभर के नामी लेखक-साहित्यकारों को वह छात्र जीवन से पढ़ती आई हैं। मुख्यमंत्री भारत मंडपम में 29वें दिल्ली पुस्तक मेला का उदघाटन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रही थीं। कुछ देर उन्होंने स्टालों का भ्रमण भी किया। इस अवसर पर दिल्ली के कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। 29वां दिल्ली पुस्तक मेला भाषायी एकता के साथ साथ देशभक्ति का भी संदेश देगा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मेले में हर घर तिरंगा... का एक सेल्फी पाइंट भी लगाया गया है। मेला दर्शक यहां तिरंगा हाथ में लेकर अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं। मेले में पहली बार प्रकाशकों के साथ साथ दिल्ली सरकार की विभिन्न अकादमियां भी हिस्सा ले रही हैं। भारत मंडपम के हाल नं. 12 और 12 ए लगने जा रहे इस मेले में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा 15 लेखक साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे। रविवार को मेले के समापन समारोह में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्यातिथि होंगे। बहुभाषिये भारत का भविष्य होगी। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आइटीपीओ) और भारतीय प्रकाशक संघ (एफआइपी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले इस मेले में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। मेले में 100 से अधिक प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। एफआइपी पदाधिकारियों के मुताबिक कमोबेश हर साल ही पाठकों और दर्शकों की शिकायत रहती है कि मेले में प्रकाशक कम जबकि पुस्तक विक्रेता ज्यादा रहते हैं। ऐसे में इस बार व्यवस्था बनाई गई है कि हाल नं. 12 सिर्फ प्रकाशकों के लिए आरक्षित है जबकि हाल नं. 12 ए में अन्य सभी भागीदारों के स्टाल हैं। मेले में पुस्तकों के लोकार्पण, संगोष्ठी, व्याख्यान एवं स्कूली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों की मेले में अधिकाधिक शिरकत सुनिश्चित करने के लिए स्कूल-कॉलेजों को पत्र भी भेजे गए हैं। एफआइपी के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया, हमारी कोशिश है कि पिछली शिकायतें दूर करते हुए इस साल इसे कहीं बेहतर रूप में आयोजित किया जाए। निशुल्क प्रवेश के साथ मेले में और भी कई आकर्षण रहेंगे। भाषायी विविधता की एकता मेले का खास संदेश रहेगा।

## पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया, यहां होंगे गृह-विदेश समेत 7 मंत्रालयों के ऑफिस

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दस नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरियट भवनों में से पहले, कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया। इस नए पावर कॉम्प्लेक्स में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग स्थित होंगे, जो वर्तमान में दिल्ली भर में स्थित हैं। कर्तव्य भवन को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले उद्घाटन किए जाने वाले कर्तव्य भवन-3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होंगे। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक स्थित मंत्रालयों को कर्तव्य भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे रेज़िन हिल स्थित दोनों ब्लॉकों को एक संग्रहालय में बदलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जहाँ भारतीय पौराणिक और आधुनिक इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। कई प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय वर्तमान में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों से संचालित होते हैं, जिनका निर्माण 1950 और 1970 के दशक के बीच हुआ था। सरकार के अनुसार, इन इमारतों को अब ÷संरचनात्मक रूप से पुराना और अक्षम÷ माना जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एचयूए) ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) के अंतर्गत दस भवनों के निर्माण की योजना शुरू की है। इनमें से भवन 2 और 3 निर्माणाधीन हैं और अगले महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। सीसीएस भवन 10 का काम अगले साल अप्रैल तक पूरा होने वाला है, जबकि भवन 6 और 7 का निर्माण अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि वर्तमान में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन में कार्यरत कार्यालयों को निर्माण चरण के दौरान दो वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से चार नए स्थानों, कस्तूरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड और नेताजी पैलेस में स्थानांतरित किया जाएगा।

## लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती, विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री रिजिजू की दो टूक

नई दिल्ली । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। इसे लेकर संसद में कई दिनों से हंगामा जारी है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और नियम ऐसे मुद्दों पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं देते जो अदालत में लंबित हैं। बुधवार को भी बिहार में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और कुछ विधेयक पारित होने के अतिरिक्त खास काम नहीं हो सका है और विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के

जरिए बड़ी संख्या में लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि लोकसभा के नियम न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं देते। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने सदस्यों से प्रमुख विधेयकों के पारित होने के दौरान बहस में भाग लेने का आग्रह किया। बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 12 अगस्त को सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर करने वाली राजनीतिक पार्टियों से भी 8 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने बुधवार को सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने 1 अगस्त को बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद से 6 अगस्त (सुबह 9 बजे) तक एसआईआर को लेकर कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

## मोबाइल छीनने का विरोध किया तो बदमाशों ने पेट में चाकू घोंपा, पेट को चीरता हुआ चाकू किडनी में जा लगा, गंभीर

बाहरी दिल्ली। आजादपुर मंडी में एक श्रमिक को मोबाइल फोन लूटने का विरोध करना काफी महंगा पड़ा। श्रमिक के पेट में चाकू मारकर आरोपित मोबाइल फोन लूटने के बाद फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घायल के पेट को चीरता हुआ, चाकू किडनी में लग गया है। इस कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना कल देर रात आजादपुर मंडी के शेड नंबर 5 और 6 के बीच की है। पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली-एनसीआर में बीते चेन स्नैचिंग और राहगीरों से लूट की खबरें अब आम हो गई हैं। ऐसे में इन चोर-उचक्कों का मन इतना बढ़ चुका है कि वे अब किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले जरा भी नहीं सोचते। हाल ही में कांग्रेस की सांसद आर. सुधा से चेन स्नैचिंग की वारदात ने सबको सकते में डाल दिया था। एक सांसद ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या ही कहना? ऐसे में दिल्ली की आजादपुर मंडी में तो मोबाइल लूटने का विरोध करने पर चाकू से हमला कर उसकी जान लेने की कोशिश पुलिस के लिए चुनौती है। फिलहाल, घायल का इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं, पुलिस मामले का खुलासा करने के लिए वारदातस्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि हमलावर चोर का कोई सुराग लग सके।

# आतंकिस्तान के साथ संधि, भारत के लिए दंड

इतिहास में कुछ घटनाएं दो बार घटती है। पहली बार हास्य के रूप में और दूसरी बार तमाशा के रूप में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही हैं। 30 जुलाई को रियलिटी टीवी होस्ट से टैरिफ तानाशाह बने ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत की आर्थिक गिरावट का बम गिराया, साथ ही कूटनीतिक झूठ का पुलिंदा बांधते हुए दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित की है। ट्रंप ने नई दिल्ली की पीठ में छुरा घोंपने के लिए इस्लामाबाद के साथ हाथापाई की। उनका यह आर्थिक हमला अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि खुद उनके लिए रचा गया है। ट्रंप पाकिस्तान के पैट्रोलियम उत्खननकर्ताओं और क्रिप्टो कार्टेलों को लुभा रहे हैं, अपनी जेबें भरने के लिए ऐसी पहलवानियों और भुगतान प्लेटफॉर्मों की योजना बना रहे है जो किसी भी जांच-पड़ताल से बच निकलेंगे। उनकी कुल संपत्ति एक साल में 60 करोड़ डॉलर बढ़ गई और उनकी नैतिकता गर्त में समा गई। यह नापाक हरकत उस व्यक्ति की ओर से हो रही है जिसने कभी डॉलर से भरे प्रवासी भारतीयों से भरे स्टेडियमनुमा तमाशे में नरेंद्र मोदी को गले लगाया था। 'सच्चा दोस्त' और 'महान नेता' कहा था। बात में लेन-देन के धुरंधर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली है जो अपने पिछवाड़े में आतंकी शिविरों को पाल-पोस रहा है। इस नापाक मुलाकात और अमेरिका ग्रेट अगेन (एमएजीए) की बड़बड़ाहट के पीछे एक ऐसा शख्स छिपा है जो नैतिकता से नहीं, बल्कि अपने संदिग्ध साम्राज्य को मजबूत करने के लिए डॉलर से प्रेरित है। पाकिस्तान के जनरल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह के साथ उनका गठबंधन कायरता की आड़ में एक सोची-समझी साजिश है जो भारत को पुराने बुरे सपनों में वापस धकेल रहा है। याद है 1971, जब रिचर्ड निक्सन ने बंगलादेश युद्ध के दौरान भारत को धमकाने के लिए दुर्जेय विमानवाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज भेजा था? इंदिरा गांधी ने पलक तक नहीं झपकाई। भारत झुका नहीं और इतिहास उसी को याद रखता है जो डटा रहा। इस बार, इतिहास एक तमाशे के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में दोहराया जा रहा है। ट्रंप लाल टाई पहने निक्सन है, जो फिर से इस्लामाबाद का साथ दे रहे हैं। इस बार बस इतना फर्क है कि अमेरिका टैरिफ और ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है लेकिन भारत तब और अब झुकने से इनकार करता है। ट्रंप का विश्वासघात एक दोधारी तलवार है। पिछले हफ्ते दागी गई उनकी टैरिफ मिसाइल, भारत के अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका को 87 अरब डॉलर के निर्यात पर निशाना साधा रही है जिससे अनुमानित 7 अरब डॉलर का नुकसान होने का खतरा है। राष्ट्रपति ने अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर भारत द्वारा लगाए गए 70 प्रतिशत शुल्क और 12 प्रतिशत व्यापार-भारित टैरिफ का हवाला देकर इसे उचित ठहराया। उन्होंने फरवरी 2025 से अब तक आठ बार भारत को 'बड़ा दुर्व्यवहार करने वाला' करार दिया है और रूस के साथ इसे एक 'मृत अर्थव्यवस्था' करार दिया है। ट्रंप ने यह भी कहने की गुस्ताखी की कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। उन्होंने झूठा दावा किया कि भारत ने 'बिना टैरिफ वाला सौदा' पेश किया, जिसका एस. जयशंकर ने खंडन किया। 'सौदे पारस्परिक रूप से लाभकारी होने चाहिए।' नई टैरिफ व्यवस्था 2017 के बाद से बने विश्वास को तोड़ती है, जब मोदी और ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मोदी के गर्मजोशी भरे आलिंगन, अहमदाबाद में ट्रंप के 2020 के 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम और आपसी प्रशंसा से चिह्नित मोदी की अमेरिकी यात्राओं के जरिए एक मजबूत रिश्ता बनाया था। 2024 तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 120 अरब डॉलर हो जाएगा। फरवरी में ट्रंप और मोदी के बीच हुई आखिरी मुलाकात में, भारतीय प्रधानमंत्री ने पारस्परिक शुल्कों से बचने के लिए टैरिफ में कटौती की पेशकश की और 2030 तक 500 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा लेकिन बाद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के युद्धविराम के झूठ, 'परमाणु युद्ध' रोकने और 'पांच जेट मार गिराए जाने' के मनगढ़ंत दावे ने पाकिस्तान की रक्षा करते हुए भारत को अपमानित किया। इसके अलावा, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनीर की मेजबानी की, जहां उन्होंने शेखी बघारी, 'मैंने परमाणु युद्ध रोका।' विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तुरंत जवाब दिया। 'मोदी ने ट्रंप को बताया कि अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं हुई।' अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच शांति 'स्थापित' करने के बारे में बड़े-बड़े झूठ बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा कि मोदी ने लोकसभा में 20 घंटे की ऐतिहासिक बहस में कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई किसी विदेशी नेता ने तय नहीं की थी।' सच तो यह है कि भारत ने ही हमले तय किए थे। पाकिस्तान में संचालित आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। मोदी आधुनिक महाभारत के योद्धा की तरह दिख रहे थे, उनके साथ जयशंकर जैसे न्यायप्रिय और राजनाथ जैसे हमलावर थे। उन्होंने उत्साह किया कि कैसे भारत की मिसाइलों ने नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और 100 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान रेंगता हुआ आया। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बड़बड़ाते हुए मोदी पर निकम्मा का आरोप लगाया लेकिन वे नासमझ लग रहे थे। उन्होंने उपहास करते हुए कहा-अगर मोदी में इंदिरा गांधी जैसा जरा भी साहस है तो उन्हें ट्रंप को झूठा कहना चाहिए। मोदी ने उन्हें झूठा नहीं कहा, बल्कि उन्हें दीवाली की तरह रोशन किया, यह बताते हुए कि कैसे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की धमकी भरी चेतावनियों को नकार दिया गया। जयशंकर ने ट्रंप के व्यापारिक कल्पित दावों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा-कोई युद्धक, कोई हस्तक्षेप, कोई झूठ टिक नहीं सकता। राजनाथ ने सटीक हमलों की प्रशंसा करते हुए कहा-हमने पहलगाम नरसंहार का बदला 22 मिनट में ले लिया। जब मोदी सैनिकों के साथ मार्च कर रहे थे तो कथित ट्रंप की पर्चियों की कहानियों को थामे हुए धराशायी हो गईं। डीएमके की कनिमोझी ने माना कि जिसके 'हमारे सैनिकों की बहादुरी को नजरअंदाज कर दिया'। मोदी की टीम संसद में अपनी बात पर अड़ी रही जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में गरजते हुए कहा-भारत के बाजार सहयोगियों के लिए है, हमलावरों के लिए नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप का जवाबी टैरिफ दोहरा झटका भारत के 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार और वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व पर लक्षित है मोदी का '2047 तक विकसित भारत' का विजन स्वायत्तता की मांग करता है, अधीनता की नहीं। यूएनसीटीएडी के अनुसार, ट्रंप के टैरिफ विकासशील देशों को वैश्विक संबंधों की ओर धकेलेंगे। भारत के फार्मास्युटिकल्स और परिधान जैसे विविध निर्यात एशिया और यूरोप की ओर बढ़ सकते हैं। ट्रंप का यह प्रयास वैश्विक दक्षिण में प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है, जिसमें भारत अमेरिकी आधिपत्य के खिलाफ ब्रिक्स का नेतृत्व कर सकता है। भारत अकेला नहीं है, ब्रिक्स उभर रहा है, आसियान देख रहा है और यूरोप पुनर्संतुलन कर रहा है। अगर ट्रंप अड़े रहे तो भारत ब्रिक्स संबंधों को और गहरा कर सकता है जिससे उन्हें एक महत्वपूर्ण सहयोगी को खोने का पछतावा होगा। ट्रंप की टैरिफ चालबाजी कूटनीतिक ब्लैकमेल में लिपटी एक दोहरी चाल है। उनका तर्क है कि भारत हार्ले और हैम पर 'उच्च शुल्क' लगाता है। ट्रंप के अस्वस्थ पांच के दांवे ने उनके ब्रांड को तो बढ़ावा दिया है लेकिन भारत, जापान, कनाडा और यहां तक कि नाटो के साथ भी उनके रिश्ते खराब कर दिए हैं। उनके झूठ और टैरिफ उनके साम्राज्य को मजबूत करते हुए एक दोस्त को धोखा देते हैं। 14 देशों पर 25-40 प्रतिशत टैरिफ लगाकर और ब्रिक्स को धमकी देकर उनका आर्थिक विस्तारवाद अमेरिका से ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है। ट्रंप का दुस्साहस अमेरिका द्वारा महंगाई प्राप्त शिक्षाविदों, नौकरशाहों, कॉर्पोरेट दिग्गजों और कुलीन सामाजिक कार्यकर्ताओं के उस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को भी कमजोर कर सकता है जो विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक फैसलों को प्रभावित करते हैं।

ट्रंप का दिखावा, मुनाफाखोरी और बेतुका झूठ उन्हें लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक वैश्विक धौंसिया के रूप में चिह्नित करते हैं। यह अमेरिका फर्स्ट नहीं है, यह ट्रंप फर्स्ट है। पाकिस्तान की ओर उनका झुकाव आतंकी नेटवर्क को नई हवा देता है। यह 1970 के दशक की रणनीति को पुनर्जीवित करता है। भारत को अलग-थलग करें, इस्लामाबाद से दोस्ती बढ़ाओ और शांति स्थापना का दिखावा करो लेकिन सफलतापूर्वक भारत कोई कमजोर देश नहीं है। यह 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ग्लोबल साउथ की आधारशिला है। वाशिंगटन को संदेश यह होना चाहिए कि भारत को लालच नहीं दिया जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा या धमकाया नहीं जाएगा। अगर राष्ट्रपति निक्सन के 'पोटस' की भूमिका निभाना चाहते हैं तो भारत एक बार फिर मोदी के 'डेविड' की भूमिका निभाएगा, गुलेल से नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत, कूटनीतिक दृढ़ता और अमेरिकी दांव से परे रणनीतिक गठबंधनों से लैस। मोदी के नेतृत्व में भारत अडिग और बेपरवाह खड़ा है। अपने 1.4 अरब उपभोक्ताओं और 120 अरब डॉलर के व्यापार के साथ, भारत सम्मान की मांग करता है। मोदी की संसदीय जीत भारत के संकल्प को प्रमाणित करती है। यह उस धौंसिया को परास्त कर देगी जिसका विश्वासघात वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। तो आगे बढ़िए, श्रीमान ट्रंप, निक्सन की भूमिका निभाइए।

# वृद्धावस्था में माता-पिता से सहानुभूति से पेश आने की सख्त ज़रूरत

भारत में हम आदि अनादि काल से सुनते आ रहे हैं कि यहां माता-पिता बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बहुत अधिक है। उन्हें ईश्वर आइक्ष की तरह देखा जाता है व मातृ-पितृ दिवस, मातृ दिवस, पितृ दिवस,बड़े बुजुर्गों का दिवस इत्यादि मनाए जाते हैं,जो बहुत अच्छी बात है परंतु मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि अब यह शब्द,गाथाएं पौराणिक कथाएं इस आधुनिक युग में केवल किताबों या शाब्दिक जुमले बनते हुए पर ठीक इसके विपरीत के सटीक उदाहरण तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी सप्ताह भर पहले ही हमने सीसीटीवी पर अयोध्या कांड देखें जहां संभवतः परिवार वाले उस 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सड़क पर यूं ही रोड पर फेंक कर चले गए थे, जो आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर है, फिर अभी चार दिन पहले केरल हाई कोर्ट में एक मामले आरपीएफसी नंबर 253/2025 अब कृष्णन मलाई 57 वर्ष बनाम जानकी अम्मा 100 वर्ष व अन्य निर्णय 2022 में फैमिली कोर्ट ने मां को 2000 रुपए प्रति माह का भत्ता देने का आदेश दिया था, जिसे पुत्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने अत्यंत तीखी टिप्पणियों के साथ अपील को खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि एक 100 वर्ष की महिला सिर्फ 2000 रुपए मासिक के लिए अपने पुत्र के खिलाफ कोर्ट में गई,वहां जीती तो पुत्र ने हाईकोर्ट में अपील की व पुत्र हार गया, अब शायद सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाना भी संभावना है,यह है एक मां का सम्मान? आज मैं यह मुद्दा इसीलिए उठा रहा हूं कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है व आज 5 या 6 अगस्त 2025 को भी सभी सांसद मिलकर अयोध्या व केरल मां केस का संज्ञान लेकर लोकसभा यानी निचले सदन के सभी 543 सदस्य व राज्यसभा यानी उच्च सदन के सभी 245 सदस्य कुल मिलाकर 788 सदस्य मिल जाएं तो माता-पिता,बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक बेहतरीन सख्त मेंटे ड्राफ्ट समायोजित भिन्न माता-पिता वरिष्ठ नागरिक (अल्पाधार अपमान दुर्व्यवहार निवारण) विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों में 788/0 मतों से पास कर विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत करें, तो सारी जनता सभी सांसदों की कृतज्ञता हो जाएगी। यह बात मैं क्लियर कर रहा हूं कि सभी बच्चे अपने माता-पिता का अपमान नहीं करते जबकि बहुत बच्चे ऐसी है जो अपने माता-पिता व बड़े बुजुर्गों पर अपनी जान निछावर करते है,परंतु कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक आम पूरे घड़े के सभी आमों को खराब कर देता है, इसीलिए समाज की उन गन्दी मछलियों व आमों को कड़ी सजा देने का वक्त आ गया है ताकि, ऐसा कार्य करने वालों को सख्त संदेश जाए,और आगे इस तरह की घटनाएं न हो इसको सरकार करने के लिए, उपरोक्त विधेयक 2025 पास करना जरूरी है, तथा उसमें हत्या रेप देशद्रोह जैसी सख्त तुल्य उम्र कैद फांसी जैसी सख्त सजा का प्रावधान हो, यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो उसे नौकरी से डिसमिस करने सहित अनेक कड़क का प्रावधान करना जरूरी है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे हाईकोर्ट जजमेंट में पुत्र को फटकार,फटकार,मैं गहरी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि 100 वर्षीय मां सिर्फ 2000 रुपए मासिक पेंशन पाने के लिए बेटे से लड़ रही है। साथियों बात अगर हम 1 अगस्त 2025 को केरल हाई कोर्ट द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक आरपीएफसी नंबर 253/2025 दिए जजमेंट की करें तो, यह एक रिवीजन पिटिशन (आरपीएफसी) नं 253 ऑफ़ 2025) थी जिसे 57 वर्ष के उ..कृष्णा पिल्लई ने दायर किया, जो अपनी 100 वर्षीय मां जानकी अम्मा की तरफ से फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहा था, जिसमें मासिक 2,000 को रख-रखाव राशि देने का निर्देश दिया गया था।फैमिली कोर्ट ने वर्ष अप्रैल 2022 में यह आदेश जारी किया था, लेकिन बेटे ने भुगतान नहीं किया, जिसके चलते रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू हो गए।पुत्र ने दावा किया कि उसकी मां उसके बड़े भाई के साथ रहती है, और उसकी अन्य संतानें उस पर निर्भर है, इसलिए केवल वही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए। उसने तर्क दिया कि वह मां की देखभाल करने को तैयार है यदि वह उसके साथ रहना स्वीकार करें। साथ ही,उसने 1,149 दिनों की देरी से फैमिली कोर्ट के रिविजन की चुनौती दी,जिसे वह न्यायिक त्रुटि बताता है।हाईकोर्ट का निर्णायक विश्लेषण(1) प्रत्येक पुत्र की व्यक्तिगत दायित्वता-- न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस 125 में आर.पी.सी. के अंतर्गत प्रत्येक पुत्र का व्यक्तिगत दायित्व होता है जो सहायता हो, चाहे मां अन्य बच्चों के साथ रह रही या न करती हो।यह कहना कि मां के पास अन्य संतानें है जो उसकी देखभाल कर सकती है ये वह पर्याप्त नहीं है वे यह इसका उत्तरदायित्व उठाने में विफल रहता है,तो यह वह मानव नहीं कहा जा सकता।(2) अदालत ने बेटे की आलोचना करते हुए कहा कि,[एक 100- साल की मां को कोर्ट में जाकर 72,000 मासिक मांगने के लिए मजबूर करना] शर्म की बात है।-मैं गहरी शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि 100- वर्षीय मां, सिर्फ 2,000रुपए मासिक पेंशन पाने के लिए अपने बेटे से लड़ रही ह (3) देरी पर विचार, लेकिन खर्च माफ़--देरी का मुद्दा -बेटे द्वारा 1,000 से अधिक दिनों के बाद पुनरीक्षण याचिका दाखिल करना-सेर अदालत ने खर्च (कास्ट्स) लगाए जाने पर विचार किया,लेकिन-नोटिस न जारी होने के कारण उसे माफ कर दिया। (4) व्यक्तिगत और सामाजिक संदेश--बेंच ने कहा कि बच्चों को उन्हीं मूल्यों को अपनाना चाहिए जो माँ ने अपनाया था-धैर्य, समझदारी, स्नेह-और वृद्धावस्था में माता-पिता से सहानुभूति से पेश आना चाहिए।हाईकोर्ट ने मानवता, नैतिकता और कानून की त्रिवेणी में यह आदेश जारी कर समाज को स्पष्ट संदेश दिया है।पुत्र हर मां की देखभाल करना दान नहीं, वह कर्तव्य है। यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डिले,बेटा-भाई-बहन की मौजूदगी , एवं खिसकने से उनके बिना-माँ को न्याय सुनिश्चितता दिलाने पर केंद्रित है।उन्होंने पुत्र को याद दिलाया कि मां ही संसार की स्कूल है और पुत्र का आचरण वही मूल्यों पर आधारित होना चाहिए जिससे वह पला है-धैर्य, प्रेम, और मानवतावा।केरल उच्च न्यायालय का यह निर्णय कानून और संवेग के संगम का प्रबल उदाहरण है, जिसने यह साफ कर दिया कि वृद्ध माता-पिता के प्रति रख-रखाव सिर्फ कानूनी आवश्यकता नहीं बल्कि मानवीय, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य भी है। इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि किसी बेटे द्वारा अपनी मां की देख-रेख में कमी करना-नोट ओनली लीगली रॉग बट मोरली रिप्रिहेंसिबल-एक्सिप्लूड सेमफुल स्थिति मानी जाएगी। साथियों बात अगर हम केरल हाईकोर्ट के जजमेंट के ऐतिहासिक मायने की करें तो,भारत के न्यायिक इतिहास में 1 अगस्त 2025 का दिन एक ऐसा संवेदनशील अध्याय लेकर आया, जिसने कानून, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के रिश्ते को गहराई से परखा। केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जिसमें एक बेटे को उसकी 100 वर्षीय मां को 2000 रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश बरकरार रखा गया, न सिर्फ न्यायिक दृष्टि से बल्कि मानवीय मूल्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस निर्णय ने उस अनदेखे, मगर सतत् ज्वलंत प्रश्न को उजागर किया-क्या वृद्धावस्था में माता-पिता को न्यायालय के दरवाजे खटखटाने चाहिए? क्या पुत्र होने का दायित्व केवल जन्मदाता का झूठा चुका देना है, या यह कर्तव्य जीवनपर्यंत है?

यह निर्णय उन सामाजिक धाराओं को भी चुनौती देता है जो यह मानती है कि वृद्धजन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में स्वयं को 'परित्यक्त' मान लें। कोर्ट ने साफ कहा कि माता-पिता को अपने बेटों से यह अपेक्षा रखना पूरी तरह जायज है कि वे उनका भरण-पोषण करें, और वह अधिकार कानून के साथ-साथ संस्कारों में भी निहित है। कोर्ट का यह कथन- यह कर्तव्य है, दया नहीं-- इस पूरे विवाद की आत्मा है। यह समाज को उसकी अंतरात्मा की ओर लौटने का इशारा करता है, जहां बेटा केवल पुत्र होने से नहीं, बल्कि पुत्रधर्म निभाने से समाज के मूल्यबोध में स्थान पाता है।एक औरमहत्वपूर्ण बात यह रही कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस दलील को भी खारिज किया जिसमें उसने कहा कि उसकी मां अन्य बेटों के साथ रहती है, और वह अकेले क्यों भुगतान करे। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों के बीच बंटवारे की बहस याचिकाकर्ता बाद में सिविल कोर्ट में कर सकता है, परन्तु फिलहाल उसके दायित्व को टाला नहीं जा सकता। यह रुख इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि यह न्याय को केवल तकनीकी व्याख्या में सीमित न रखकर मानवीय संदर्भ में प्रस्तुत करता है।

यह मामला भारतीय न्यायशास्त्र में कर्तव्यपरक न्याय का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न मिसालों जैसे कि कोलिकाता द. वड़ोदरिया बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात या विजीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि माता-पिता की देखभाल केवल सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह एक संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। इस निर्णय ने इन विचारों को और अधिक स्पष्टता और दृढ़ता प्रदान की है।

एक ओर यह निर्णय वृद्धजनों के पक्ष में नीतिगत निर्णयों को बल देता है, वहीं दूसरी ओर यह समाज के लिए चेतावनी भी है। आज की पीढ़ी को यह समझना होगा कि माता-पिता की सेवा केवल धार्मिक अनुष्ठानों या धार्मिक पितृपक्ष में श्राद्ध करने तक सीमित नहीं है। वास्तविक श्रद्धा और सेवा तो तब होती है जब माता-पिता जीवित हों और उन्हें अपने बच्चों की सहायता की जरूरत हो।

किसी मां को 2000 के लिए अदालत में जाना पड़े,यह स्थिति खुद समाज की विफलता है। साथियों बात अगर हम इस एक सदस्यीय बेंच की तारीफ एक काबिल जजमेंट की करें तो, न्यायमूर्ति की कलम ने जिस प्रकार भावनात्मक गहराई और कानूनी अनुशासन के संतुलन को साधा है,वह इस निर्णय को सामान्य अदालती फैसले से ऊपर उठाकर आंदोलनात्मक दृष्टांत में परिवर्तित करता है। यह निर्णय हर कानून के विद्यार्थी, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर नीति निर्धारक और हर संतान के लिए एक नैतिक पाठ है।इस निर्णय को भारत के विद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों और प्रशासनिक संस्थानों में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।

सम्पादकीय...

# हादसों पर लगे लगाम

हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की सुर्खियों की स्याही अभी सूखी नहीं कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से भी भगदड़ की खबर आ गई है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि तकनीक और सहूलियतों से देश लैस होता जा रहा है। इस संदर्भ में जब भगदड़ की घटनाएं सामने आती है तो आधुनिकता से कदमताल करने वाली ये छवियां दरकने लगती है। ऐसा नहीं कि देश का ध्यान इस विरोधाभास की ओर नहीं है। फिर भी ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं। ऐसी घटनाएं जब भी होती है तो एहतियाती कदम उठाए जाने की प्रशासनिक तंत्र की ओर से घोषणाएं होती है। कुछ दिन में देश ऐसी घटनाओं को भुला देता है। अभी भूलने और भुलाने का यह खेल जारी ही रहता है कि कोई नई घटना आ जाती है और एहतियाती कदमों का ऐलान महज हवा-हवाई बनकर रह जाता है। भगदड़ की घटनाओं को लेकर अपनी व्यवस्था कितना संजीदा है, इसी साल हुई घटनाओं से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। साल 2025 में ही सात घटनाएं हो चुकी है, जिनमें आधिकारिक तौर पर 81 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि सैकड़ों घायल हुए हैं। दिलचस्प यह है कि ये घटनाएं कुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन में तो हुई ही, राष्ट्रीय राजधानी के रेलवे स्टेशन से लेकर गोवा जैसे कम जनसंख्या वाले राज्य में भी घटीं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नई सदी के बाइस साल में 23 बार भगदड़ मची, जिनमें करीब डेढ़ हजार लोगों को जान गंवानी पड़ी। इन घटनाओं में घायल लोगों में से कई दिव्यांग बन गए तो कई को ऐसा मानसिक आघात लगा कि उससे अभी तक उबर नहीं पाए है। भगदड़ की घटनाओं के लिए नागरिक बोध की कमी को पहला कारण माना जाता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि भगदड़ की ज्यादातर घटनाएं प्रशासनिक तंत्र की खामी की वजह से होती है। मसलन, 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटी घटना की वजह रेलवे अधिकारियों की सोच रही, जिन्होंने आनन-फानन में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया और उसमें जगह पाने के लिए लोग दौड़ पड़े। दुनिया की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अधिकारियों का कल्पनाशील और अनुमानशील होना जरूरी माना जाता है। लेकिन भारतीय प्रशासनिक ढांचे इस कल्पनाशीलता की अक्सर कमी नजर आती है। उसे भावी संकटों और समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए जरूरी सोच की कमी है। वह किसी समस्या का अंदाजा लगाकर उसे शुरू में रोकने और व्यवस्थित करने की बजाय आखिरी छोर पर निबटने की सोच से लगातार लैस रहता है। मेले-ठेले में जाने वाले लोगों की भीड़ को मेले में घुसने से पहले व्यवस्थित करने और उसे रोकने में भारतीय प्रशासनिक तंत्र की दिलचस्पी कम होती है, लेकिन जब मेले में भीड़ बढ़ जाती है तो मेले वाली जगह के दरवाजे पर वह अचानक से रोक लगा देता है। जबकि होना यह चाहिए कि मेले की ओर जाने वाले रास्ते पर भीड़ को देखते हुए रोक लगा दी जाए। दरवाजे पर भीड़ को रोकने से मेले में भीड़ भले ही ना घुसे, लेकिन पीछे से आ रहे रेले पर रोक नहीं लग पाती। इससे बैरिकेट वाली जगह पर भीड़ का दबाव बढ़ जाता है। पीछे वाली भीड़ के दबाव के चलते एक वक्त ऐसा आता है कि बैरिकेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर रेला लोगों को धकियाते आगे बढ़ने लगता है। इस बीच कोई गिर गया तो पीछे वाले के पास ना तो इतना वक्त होता है कि वह संभल पाए ना ही इतनी क्षमता कि पीछे वाली भीड़ को रोक पाए। वह सामने गिरे व्यक्ति के शरीर की ओर अपना पैर बढ़ने से रोक भी नहीं पाता। इसी दौरान गिरे हुए लोग दूसरे लोगों के पांवों से कुचलते चले जाते है। प्रयागराज की भगदड़ की भी वजह यही थी। भीड़ पीछे नहीं रोकी गई, स्नान केंद्र के पास रोकी गई। इसकी वजह से बैरिकेट पर दबाव बढ़ा और पीछे से आए रेला ने इसकी परवाह नहीं कि कौन गिरा है और किसके पेट,पीठ या सिर पर उसका पैर पड़ रहा है। भगदड़ के बारे में एक अवधारणा रही है कि गरीब-गुरबा और अशिक्षित लोग ही इसके शिकार बनते हैं। लेकिन यह अधूरा सच है। यह सच है कि उत्तर भारत के मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ में ज्यादातर निम्न मध्यम वर्ग के लोग होते है। उत्तर भारत में मंदिरों तक में वीआईपी संस्कृति का बोलबाला है। इसकी तुलना में दक्षिण भारतीय मंदिरों में वीआईपी संस्कृति कुछ कम है। हालांकि दक्षिण के भी कई मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था में वीआईपी संस्कृति का तड़का रहता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्तर में यह संस्कृति ज्यादा है। इसलिए उत्तर के मंदिरों और धार्मिक मेले-ठेले में अनुशासनहीन भीड़ की बहुलता होती है। चूंकि प्रशासनिक तंत्र कल्पनाशीलता से उन्हें व्यवस्थित नहीं कर पाता, लिहाजा भगदड़ की दुर्भाग्यजनक घटनाएं हो जाती है। इसमें दो राय नहीं कि भारत की एक बड़ी समस्या भारत की बड़ी जनसंख्या भी है। हालांकि आज की राजनीति का एक हिस्सा इसे समस्या नहीं मानती। क्योंकि उसका आधार वोट इसी भीड़तंत्र से ही विकसित होता है। भारत में एक बड़ी समस्या यह है कि भीड़ को अनुशासित करने का संस्कार और शिक्षण पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर नहीं है। इसकी वजह से मौका पाते ही हर व्यक्ति रसूख के साथ भीड़ से निकलना चाहता है या फिर अपना वर्चस्ववादी स्वभाव दिखाना चाहता है। प्रशासनिक तंत्र इस मानस के आगे कभी रसूख देख झुक जाता है तो कभी वह सोच भी नहीं पाता कि इसके नकारात्मक असर क्या-क्या हो सकते है। ऐसे में कई बार पिछड़ती हुई भीड़ अपना आपा भी खो देती है। भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी तक चूंकि गरीबी की मार झेलता रहा है, इसलिए उसके अवचेतन में कुछ पाने की चाह में दूसरों को पीछे छोड़ने की सोच हावी रहती है। इसमें अगर अफवाह अगर मिल जाती है तो हालात भयावह हो जाते है। कह सकते है कि संस्कार और सोच की कमी, व्यवस्था को सुचारू बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले तंत्र की कल्पनाहीनता और घनी जनसंख्या का कोलाज के सामने उनके बेपटरी होने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसा जब होता है तो हादसों के रूप में उसका भयावह नतीजा सामने आता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि देश के भीड़भाड़ वाले आयोजन बिना किसी भगदड़ या अव्यवस्था के संपन्न हो सकें। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मुकम्मल नीति बनाने और उसे कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। हमें पता है कि आज के दौर की हर कठिन राह को तकनीक ने आसान की है। इसने तमाम समस्याओं के समाधान की नई राहें भी निकाली है। नीतिगत स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाना होगा। प्रशासनिक तंत्र को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना होगा कि तकनीक के इस्तेमाल से वे ठीक से पता लगा पाएं कि किस बिंदु पर भीड़ को रोका जाना चाहिए, कहां बैरिकेटिंग करके भीड़ को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

# पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग

पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिन्दूर पर संसद के दोनों सदनों में हुई गर्मागर्म बहस के दौरान जिस प्रकार पाक अधिकृत (गुलाम) कश्मीर का मुद्दा उठा उससे एक बार फिर साबित हो गया कि भारत कश्मीर के इस हिस्से को लिये बिना चैन से नहीं बैठेगा। वैसे तकनीकी तौर पर देखा जाये तो यह हिस्सा भारतीय संघ का आज भी हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने 1948 में हड़प लिया था। कश्मीर में पाकिस्तान की स्थिति एक आक्रमणकारी देश की है , यह भी 1949 में भारत ने राष्ट्रसंघ में सिद्ध कर दिया था। जम्मू-कश्मीर रियासत के 26 अक्तूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय के समय जिस प्रकार पाकिस्तान ने अपने सशस्त्र कबायलियों को कश्मीर पर हमला करने भेजा था उसकी पोल भी राष्ट्रसंघ में 1949 में खुल गई थी क्योंकि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया था कि उसकी सेनाओं ने भी कश्मीर के मोर्चे पर भारत की सेनाओं का मुकाबला किया था। मगर दिसम्बर 1947 में ही भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री स्व. पं. जवाहर लाल नेहरू इस मसले को लेकर राष्ट्रसंघ में चले गये थे जिसकी वजह से कश्मीर समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय करण हो गया था। इसके बाद राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद ने 1948 में हस्तक्षेप किया और 30 दिसम्बर 1948 को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई मगर तब तक कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। इसके बाद जनवरी 1949 में राष्ट्रसंघ ने पूरे जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह इसके द्वारा नियुक्त आयोग की निगरानी में कराने का प्रस्ताव पारित किया। पं. नेहरू ने ही शुरू में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव किया था। 7 जनवरी 1949 को आयोग ने जनमत संग्रह कराने की शर्तों को प्रकाशित भी कर दिया। उस समय नेशनल कान्फ्रेंस के नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्यमन्त्री थे। पाकिस्तान ने शर्त रखी थी कि जनमत संग्रह से पूर्व शेख अब्दुल्ला की सरकार को पदमुक्त किया जाये और रियासत में तैनात भारतीय सेना को भी हटाया जाये। मगर भारत ने इन दोनों शर्तों को मानने से इंकार कर दिया था। मूल प्रस्ताव में यह शर्त थी कि पाकिस्तान गुलाम कश्मीर से अपनी सेनाएं हटायेगा और भारत को यह हक होगा कि वह चुनाव या जनमत संग्रह कराने के लिए आवश्यक सरकारी अमला व फौज को रखे। उस समय के अखबारों में 8 जनवरी 1949 को छपा था कि ''संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ने जनमत संग्रह की शर्तों को प्रकाशित कर दिया है जिसके आधार पर यह निर्णय किया जायेगा कि जम्मू-कश्मीर रियासत भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसके साथ शामिल होगी। आयोग की शर्तों से स्पष्ट हो जाता है कि जनमत संग्रह पूरी तरह निष्पक्ष व स्वतन्त्र होगा। जब पं. जवाहर लाल नेहरू ने जब शुरू में जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने किसी मानसिक संकोच या दुराव-छिपाव से काम नहीं लिया था'। कमीशन के प्रस्ताव में यह शर्त भी थी कि जनमत संग्रह व्यवस्थापक को राष्ट्रसंघ ही मनोनीत करेगा मगर उसकी नियुक्ति की घोषणा जम्मू-कश्मीर की शेख अब्दुल्ला सरकार ही करेगी और मतसंग्रह के लिए उसे जरूरी अधिकार भी राज्य सरकार ही देगी। मत संग्रह व्यवस्थापक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ऊंची ख्याति होगी और जिस पर सभी को विश्वास होगा। भारतीय फौज भी रियासत में बनी रहेगी। उसे कहां-कहां और कितनी संख्या में रखा जायेगा इसका फैसला सूबे की सुरक्षा और जनमत संग्रह की स्वतन्त्रता को ध्यान में रख कर किया जायेगा।' पाकिस्तान चाहता था कि उसकी फौजें भी जम्मू-कश्मीर में रहे और शान्ति-व्यवस्था बनाने में उनकी भी मदद ली जाये। इसे एक सिरे से नकार दिया गया। इस घटना क्रम का यदि आज विश्लेषण किया जाये तो हम पायेंगे कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर का जो इलाका हड़प रखा है वह शत-प्रतिशत रूप से भारत का ही हिस्सा है और 26 अक्तूबर 1947 को भारतीय संघ में हुए इसके विलय का चीखता हुआ प्रमाण है। आज का दीगर सवाल यह है कि भारत इस इलाके को किस प्रकार भारतीय संघ में समाहित करे। इस सिलसिले में 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किया जाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण पड़ाव है। संविधान में यह अनुच्छेद सिर्फ जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में ही जोड़ा गया था और यह काम संविधान सभा में ही हुआ था। इसे मूल रूप में ही अखंड रखा गया था। इसे समाप्त करने से पिछली सरकारों के कदम डगमगाते थे क्योंकि इस सूबे के क्षेत्रीय दल इस मुद्दे पर केन्द्र से सीधे भिड़ जाते थे और धमकियां देने पर उतारू हो जाते थे। साथ ही अलगाववादी ताकतें अलग से सक्रिय हो जाती थीं। मगर वर्तमान मोदी सरकार के गृहमन्त्री श्री अमित शाह ने सभी प्रकार की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए यह ऐतिहासिक कार्य कर डाला और कश्मीर के विलय को अन्य राज्यों के समकक्ष ही रखा। इसके बाद राज्य की परिस्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन आना शुरू हुआ। जिसकी वजह से राज्य में पर्यटकों की संख्या में साल दर साल इजाफा होता रहा। ऑपरेशन सिन्दूर पर संसद में हुई बहस के दौरान भी गुलाम कश्मीर का मामला सामने आया और गृहमन्त्री ने पुरजोर तरीके से ऐलान किया कि एक न एक दिन यह भारत में मिल कर रहेगा। गृहमन्त्री तो यहां तक कह गये कि कांग्रेस की सरकारों ने इसे पाकिस्तान को दिया मगर भाजपा सरकार इसे वापस लायेगी। दर असल यह संकल्प का मामला है क्योंकि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही यह प्रतिबिम्ब होता है। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को जिन्दा रखने के लिए ही अपनी सेनाओं को अभी तक पलाइन्ड्रोस है। तभी तो कहा जाता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ऐसा एकमात्र देश है जिसकी सेना नहीं है बल्कि ऐसी फौज है जिसका अपना मुल्क है। इस बात का मतलब बहुत गहरा होता है जो पाकिस्तान को एक नाजायज मुल्क घोषित करता है। पाकिस्तान ने पिछले 76 सालों के दौरान गुलाम कश्मीर के जन भूगोल को ही बदल कर रख दिया है। गुलाम कश्मीर से कश्मीरी बोलने वाले कम होते जा रहे है । यहां के कश्मीरी लोगों के मानवीय अधिकारों को कदम-कदम पर कुचला जाता है। इसलिए रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह का यह कथन फिजूल नहीं है कि एक दिन ऐसा भी आयेगा जब गुलाम कश्मीर के लोग खुद भारत में मिलने की अलख जगायेंगे। दर असल पिछले 77 सालों के दौरान ऐसे भी कई मौके आये है जब कश्मीर समस्या का हल होते-होते रह गया। एक अवसर स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी आया था।

# वाह! क्या बात है

वाह! क्या बात है। सचमुच में दादा-दादी, पोता-पोती, नाना-नानी-नातियों का गजब का रिश्ता है। कहते है जिस घर में दादा-दादी होते है उन घरों के बच्चे बहुत ही संस्कारी नैतिक मूल्य रखने वाले होते हैं। क्योंकि दादा-दादी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सिखाते भी है और लाड़-प्यार भी बहुत करते है। इसीलिए हमने इन्हीं रिश्तों को जग जाहिर करने के लिए नए-नए अनुभव, नए-नए दादा-दादी के रिश्तों के प्यार को दर्शाने के लिए वीडियो भेजने को कहा। सभी वीडियो एक से एक बढ़कर है। क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है। नई-नई बातें रखी है। कई वीडियो तो ऐसी है जिसे देखकर समझ ही नहीं आ रहा इतने छोटे बच्चे अपने दादा-दादी से लाड़-प्यार में कैसे सीख रहे है। अभी-अभी मैंने अंजना मल्होत्रा 62 वर्षीय की अपने पोते-पोती रुहान और इनाया पश्चिम विहार की देखी। इतने छोटे पोते और छोटी सी गुड़िया से इतने मंत्र, भजन, मां के मंत्र, शिव तांडव, महामृत्युंजय मंत्र जाप सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई। इसमें उनकी मां का भी बहुत बड़ा हाथ दिखा, जिनकी आवाज भी बैकग्राउंड में सुन रही थी। जिनकी मां इतनी संस्कारी वाली हो, जिसने अपने बच्चों को दादी से जोड़ा है। धन्य है वो मां, दादी और पोते-पोती की अभी तक वीडियो मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मैं इन सबसे जरूर मिलूंगी। विजय कपूर रोहिणी शाखा अपनी पोती को देशभक्ति गीत से नैतिक शिक्षा देकर उत्साहित कर रहे है। सरला भाटिया पश्चिम विहार पोते के संग गायत्री मंत्र से अच्छी बुद्धि की कामना करते हुए श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। जाटी कलां, सोनीपत की शाखाध्यक्ष कमलेश देवी अपनी पोती को संस्कारों की शिक्षा देते हुए सनातन धर्म के अच्छे गुणों से परिचय गीत गा रही है। राकेश एवं सविता चोपड़ा रोहिणी ब्रांच के अनुसार वरिष्ठजन कभी-कभी अपनी याददाश्त खो बैठते है, उनकी याददाश्त पोते-पोतियां वापिस लाने में कैसे मददगार हो सकते है। कमाल ही कर दिया इस वीडियो में तो एक टॉप को छू लिया है। रोहिणी की कलावती केसरी अपनी बेटी, नातिन के साथ बहुचर्चित गीत गाते एक्शन पर डांस करके आनंद ले रही है। उनसे सरल्कार होना चाहिए। क्षितिज मोहिनी ने स्वतंत्रता दिवस पर बेटी के साथ देशप्रेम गीत से सबको नया जोश दिला रही है। वीना अरोड़ा, पश्चिम विहार अपने पोते के एकम को राष्ट्रीय, जनरल नॉलेज के साथ ज्ञानवर्द्धक विचार दे रही है। कलावती केसरी अपने 5 पोते-पोतियों के साथ खेलकूद के साथ देश का मान बढ़ाते हुए समय का सदुपयोग की दिशा दे रही है। मॉडल टाउन से प्रवीण अपनी बेटियों के मस्ती भरे डांस से खुशियां बांट रही है। दुर्गा भाटिया रोहिणी ब्रांच अपनी पोती के साथ भ्रमण, छुट्टियों का आनंद ले रही है। कविता रिजवानी अपनी पोतियों के साथ कत्थक डांस करते वाह! क्या बात है। गर्मी की छुट्टियों का मजा ले रही है। कृष्णा धानिया, रोहिणी की श्रीकृष्ण भजन के भक्तिमय संसार में खो गई है। शकुंतला देवी (71) पश्चिम विहार पोते-पोती के साथ रूठने-मनाने के दौरान गेम खेलते खुशियां बांट रही है। यही नहीं नेहला ब्रांच की निर्मला स्वामी 65 वर्षीय ने अपने पोते के साथ मिलकर नारी के बारे में व्याख्यान किया है। वाह! क्या बात है निर्मला जी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सदर पंचशील एन्क्लेव, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00882)

# हरियाणा के खेल मंत्री दिखे एक्शन मोड में दिखे

पानीपत।

## हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल से चंडीगढ़ जाते वक्त पानीपत स्थित छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में किया औचक निरीक्षण पलवल के बाद पानीपत के शिवाजी स्टेडियम का किया निरीक्षण।

मिशन ओलंपिक 2036 में हरियाणा से ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हों और प्रदेश के सभी स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं की कमी ना हो, इसी को लेकर मंत्री गौरव गौतम लगातार स्टेडियम का निरीक्षण कर रहे है और खेल अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे रहे है। इसी की दृष्टिगत खेल मंत्री गौरव गौतम ने बुधवार को पानीपत के शिवाजी स्टेडियम का निरीक्षण किया और विभिन्न अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं से किसी भी तरह से वंचित न रखा जाए अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की साफ मंशा है कि हरियाणा की मेडल लाने में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री गौरव गौतम ने स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों से भी कोच में सुविधाओं को लेकर भी जानकारी ली। मंत्री गौरव गौतम ने कमियों को देख, खेल अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया किसी भी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान स्टेडियम में कुछ छोटी-मोटी कमियां पाई गईं, जिनके समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी खेल सुविधाएँ समयबद्ध तरीके से दुरुस्त की जाएँ और खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने खिलाड़ी बच्चों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें 2036 ओलंपिक में हरियाणा के लिए 36 मेडल लाने के संकल्प के लिए प्रेरित किया।

उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से हर संभव सहयोग मिलेगा। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायब सैनी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश में खेलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा के होनहार खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देना हमारा दायित्व है। उन्होंने बच्चों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की।

# हरियाणा करेगा 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी की मेजबानी

## 7 से 9 नवंबर तक गुरुग्राम में होगा सम्मेलन

चंडीगढ़ ।

हरियाणा प्रतिष्ठित 18वें शहरी गतिशीलता भारत (यूएमआई) सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन 7 से 9 नवंबर, 2025 तक गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। यूएमआई कॉन्फ्रेंस केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के तत्वावधान में होने वाला एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह सम्मेलन शहरी परिवहन एवं गतिशीलता के क्षेत्र में उभरते मुद्दों, रुझानों, नवाचारों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए हितधारकों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मंच के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव श्री रस्तोगी ने कहा कि इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी हरियाणा के लिए गर्व की बात है। यह सम्मेलन सतत शहरी विकास, स्मार्ट परिवहन समाधानों और बुनियादी ढाँचे के नवाचार में राज्य की प्रगति को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय 'शहरी विकास और गतिशीलता सम्पर्क' है, जो नियोजित शहरी विकास और कुशल परिवहन प्रणालियों के बीच महत्वपूर्ण इंटरलिंकेज पर केंद्रित है। सम्मेलन में पूर्ण सत्र, तकनीकी सत्र, पैनल चर्चाएँ और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियाँ शामिल होंगी, जिनमें भारत समेत विभिन्न देशों के नीति-निर्माता, उद्योग जगत से विशेषज्ञ, शोधकर्ता और प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्य सत्रों के अलावा, इस कार्यक्रम में तकनीकी भ्रमण और धरोहर स्थल भी शामिल होंगे, जिनमें प्रतिनिधियों को क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और शहरी परिवहन पहलों की झलक देखने को मिलेगी।

# सेमग्रस्त क्षेत्र को सेममुक्त करने के लिए विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करें : श्याम सिंह राणा

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सेमग्रस्त क्षेत्र को सेममुक्त करने के लिए विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करें। उन्होंने चरखी दादरी जिला में एक खास पायलट प्रोजेक्ट शुरू करके यथाशीघ्र लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। श्री राणा आज यहां विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक श्री राजनारायण कौशिक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में वर्ष 2025-26 हेतु करीब एक लाख एकड़ लवणीय भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि विभाग तथा मत्स्य विभाग मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य में काफी भूमि सेमग्रस्त तथा लवणीय है जिसमें फसल पैदा नहीं होती है। उन्होंने अधिकारियों को सेमग्रस्त भूमि में तालाब बनाकर झींगा मछली के पालन की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल से जमीन का लवणीय पानी निकलने पर जहां भूजल स्तर नीचे जाने से क्षेत्र सेममुक्त हो जाएगा, वहीं झींगा के पालन से किसानों को अच्छी खासी आमदनी भी होगी। उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए ड्रेन के माध्यम से पानी की निकासी करने के लिए आपदा एवं प्रबंधन विभाग तथा सिंचाई विभाग के साथ तालमेल करने के निर्देश दिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए काम करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बजट में की गई घोषणाओं पर प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

# रक्षाबधंन का तोहफा: महिलाएं और 15 वर्ष तक के बच्चे रोडवेज बसों में करेंगे निशुल्क यात्रा, सरकार ने दी स्वीकृति

चंडीगढ़ ।

हरियाणा में रक्षाबंधन के दौरान महिलाएं और 15 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे मुफ्त में सफर करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने घोषणा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। विज ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के दिन सभी आयु वर्ग की महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों को राज्य सहित चंडीगढ़ व दिल्ली तक चलने वाली हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है ताकि महिलाएं व बच्चे रक्षाबंधन के पर्व पर आवागमन कर सकें। परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं और बच्चों के लिए दिनांक 8 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे से दिनांक 9 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि 12 बजे तक निशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि ''मेरे संज्ञान में आया है कि प्राइवेट बसों के रूट का निर्धारण ठीक ढंग से नहीं हुआ है और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को इन रूटों के समय को लेकर अध्ययन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं''। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि नई बसों, विशेषतौर पर इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की प्रक्रिया जारी है। विज बुधवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। मंत्री विज ने कहा कि प्राईवेट बसें सरकारी बसों से कुछ समय पहले चलती हैं और प्राईवेट बसें सवारियों को उठा लेती हैं जिससे सरकारी बसों को सवारी नहीं मिलती। इस संबंध में उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार के मामलों की जांच की जाए और अध्ययन किया जाए। इसके अलावा, विभाग के अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि इन रूटों के समय को बदला जा सकता है। इसके अलावा, मंत्री विज ने कहा कि हरियाणा के निवासियों की सुविधा के लिए यह भी फैसला लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक गांव में हरियाणा रोडवेज की बस जाएगी। राज्य के सभी गांवों में बस को पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। इस बारे में राज्य के सभी परिवहन विभाग के महाप्रबंधकों को एक पत्र भी जारी कर दिया गया है।

# राष्ट्र टाइम्स के 45वें स्थापना दिवस पर प्रकाशित स्मारिका भेंट कर वरिष्ठ साहित्यकारों का सम्मान

नई दिल्ली (साहिल गौड) दिल्ली से प्रकाशित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र राष्ट्र टाइम्स के 45वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित स्मारिका को एक विशेष भेंट स्वरूप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित मुलाकात के अवसर पर प्रख्यात साहित्यकारों को समर्पित किया गया। इस अवसर पर जाने-माने कवि श्री सुरेश नीरव तथा सुप्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती मधु मिश्रा को राष्ट्र टाइम्स के संपादक श्री विजय शंकर चतुर्वेदी द्वारा स्मारिका के साथ शॉल, प्रतीक चिह्न भेंट कर ससम्मान सम्मानित किया गया। यह भेंट न केवल साहित्यकारों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक थी, बल्कि पत्रकारिता और साहित्य के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में भी देखी गई। श्री चतुर्वेदी ने इस अवसर पर कहा- साहित्य और पत्रकारिता समाज के दो नेत्र है – दोनों का दायित्व है सत्य, संवेदना और विचारों को जन-जन तक पहुँचाना। कार्यक्रम का उद्देश्य था उन वरिष्ठ रचनाकारों को सम्मानित करना, जिनका लेखन जनचेतना को जागृत करता है और समाज के बौद्धिक विमर्श को समृद्ध करता है।



# दिल्ली सरकारो के उदासीन रवैया के कारण आदिवासी अपनी पहचान के लिए मोहताज है

## अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर नांगलोई में शोभायात्रा निकाली

नई दिल्ली ( ए, के, चौधरी) संवाददाता,अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज,रजि व सर्व धानका समाज नांगलोई के संयुक्त तत्वावधान में शोभायात्रा कलश यात्रा का आयोजन नांगलोई क्षेत्र में किया गया, इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद योगेंद्र चंदोलिया थे व विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ प्रामर्शदाता व पूर्व न्यायाधीश प्रकाश कुमार उइके,निगम पार्षद श्रीमती हेमलता राजेंद्र लाडला, आदमजाति सेवक संघ के कार्यलय सचिव रविकांत झा थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्व धानका समाज नांगलोई के अध्यक्ष नाथूलाल मोरवाल ने की, व संचालन अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र खर्रा ने किया।कार्यक्रम आरंभ डॉ भीमराव अंबेडकर और स्वर्गीय श्री डलचंद आर्य को पुष्पांजलि देकर किया गया,

इस अवसर पर प्रकाश कुमार उइके ने आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा आजादी के समय से दिल्ली में रहने वाले आदिवासी आज भी पहचान के मोहताज है, सरकारो के उदासीन रवैया के कारण दिल्ली में आदिवासियों की संख्या शुन्य है, दिल्ली सरकार को आदिवासियों की अलग से गणना करानी होगी,श्रीमती हेमलता ने कलश यात्रा में आने वाली महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि पिछले कई वर्षो से अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर महिलाओं की भागीदारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

राजेंद्र लाडला ने इस अवसर पर नांगलोई की धानका समाज को अपनी परंपराओं से जुड़े रहने के लिए अभिनंदन किया, रविकांत झा ने आदिवासियों के अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा की दिल्ली में आदिवासियों की जनसंख्या की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे आदिवासी भी दिल्ली के सभी नागरिकों के समान अपने संवैधानिक अधिकार का लाभ उठा सकें।

राजेंद्र खर्रा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा की विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए धानका समाज प्रयास कर रहा है ,हम आज भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को सम्हाले हुए है।

शोभा यात्रा कलश यात्रा में महिलाओं का उत्साह देखने योग्य था, बैंड बाजे और डीजे की धुन पर सर पर कलश लिए महिलाएं नृत्य करती नजर आ रही थी जिसके कारण पूरी शोभायात्रा में हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। छोटे-छोटे बच्चों द्वारा आदिवासी वेशभूषा क्षेत्र के लोगों को आकर्षित किया आदिवासियों की बनाई झांकी देखने को लोग उसे उत्साहित नजर आ रहे थे ,जगह-जगह सड़क के दोनों और खड़े लोगों को महिलाओं व झांकियां पर लोग फूल बरसा कर अभिनंदन कर रहे थे तो भिन्न समाज के लोगों ने जगह-जगह पानी, शरबत व जलपान की व्यवस्था कर शोभायात्रा के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे।

इस अवसर पर सर्व धानका का समाज नांगलोई के महासचिव ताराचंद बमनिया, महेंद्र कुमार मांवर,राजेश देहराणे, सुरेन्द्र मांवर, कर्ण बमनिया, मुकेश निनानिया,राजकुमार डाबला, मुकेश खर्रा सहित अनेक लोगों ने व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभाई। समारोह में अजीज खान,शशि सारसर, चेतन पिपोलिया ,प्रवीण बैरवा, विनीत कुमार, रंजीत कुमार ने अहम भूमिका निभाई।

# राज्यसभा में पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक को दी गई श्रद्धांजलि

नई दिल्ली । राज्यसभा में बुधवार को पूर्व सदस्य दिवंगत सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। मलिक का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को नयी दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति ने मलिक के निधन का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने उच्च सदन में उत्तर प्रदेश का दो बार, 1982 से 1989 तक प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई 1946 को जन्मे मलिक ने नौवीं लोकसभा में अलीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। हरिवंश के अनुसार, उप्र विधानसभा के सदस्य रह चुके मलिक ने चार राज्यों - बिहार (2017), जम्मू और कश्मीर (2018), गोवा (2019) और मेघालय (2020) के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। उपसभापति ने कहा कि मलिक के निधन से देश ने एक बेहतर प्रशासक, एक उत्कृष्ट पूर्व सांसद तथा एक मुखर राजनीतिक नेता को खो दिया है। सदन में मौजूद सदस्यों ने मलिक के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

## संसद में सरकार के जवाब : सीएपीएफ और असम राइफल्स में भेदभाव नहीं; दिल्ली में सीसीटीवी व फेस रिकग्निशन सिस्टम की तैनाती

नई दिल्ली।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से मौजूदा नियमों और पात्रता मानदंडों के अनुसार हो रही है। इसमें गोरखा समुदाय समेत सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी), सब-इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट जैसे पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के जरिए की जाती है।वहीं अन्य नॉन-जीडी पदों की भर्ती संबंधित बलों की तरफ से स्वयं, उनके नियमों के अनुसार की जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई शिकायत सरकार के संज्ञान में नहीं आई है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत शहर में महिलाओं और आम जनता की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना के तहत शामिल प्रमुख पहलू सी4आई सिस्टम (इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सेंटर)

की स्थापना और पूरे दिल्ली एनसीटी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की तैनाती की जाएगी। वहीं फेस रिकग्निशन सिस्टम (चेहरा पहचानने की तकनीक) को कुछ विशेष कैमरों में लागू किया जा रहा है, ताकि संदिग्ध या वांछित अपराधियों की पहचान की जा सके। दिल्ली पुलिस ने इस तकनीकी प्रणाली के संचालन को लेकर एक स्थायी आदेश भी जारी किया है, ताकि इसके उपयोग में पारदर्शिता और नियमन सुनिश्चित हो सके। वहीं मामले में राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वर्ष 2020 से 29 जुलाई 2025 तक कुल 301 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में सजा दिलाने की दर 97.08% है, जो बताता है कि एजेंसी के कामकाज में कितनी मजबूती और सटीकता है। यह जानकारी उन्होंने एक सवाल के जवाब में दी, जिससे यह भी साफ होता है कि आतंकवाद और संगठित अपराधों के खिलाफ केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां कठोर और प्रभावी कार्रवाई कर रही हैं।

साथ ही सीआरपीएफ के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि सीआरपीएफ (सीआरपीएफ) की बटालियन कैंपिंग साइट बिहार के औरंगाबाद में अब संचालित हो रही है, और वहां रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की एक कंपनी तैनात है। उन्होंने कहा कि यह कैंप सरकार द्वारा मंजूर किए गए 25 बटालियन कैंपिंग साइट्स में से एक है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जा रहा है। अब तक इस कैंप में 120 जवानों के लिए एक बैरक और चारदीवारी का निर्माण पूरा हो चुका है।

# धराली त्रासदी- 5 लोगों की मौत

**11 जवानों समेत 100 से ज्यादा लापता, 400 का रेस्क्यू; केरल के 28 टूरिस्ट का सुराग नहीं**

देहरादून।



उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जारी भारी बारिश के बीच बुधवार सुबह धराली में आपदा पीड़ितों की तलाश के लिए बचाव एवं राहत कार्य फिर शुरू किया गया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। मंगलवार दोपहर बाद बादल फटने से खीरगंगा नदी में आयी भीषण बाढ़ में करीब आधा गांव तबाह हो गया था। धराली गंगोत्री धाम से करीब 20 किलोमीटर पहले पड़ता है और यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना स्थल पर आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बीआरओ की टीमें बचाव अभियान चला रही है। अधिकारी के अनुसार, अब तक 150 लोगों को बचाया जा चुका है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसेन शहीदी ने बचाव अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए

**उत्तरकाशी जिले में भीषण बाढ़, बचाव एवं राहत कार्य शुरू**

कहा, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बीआरओ की टीमें घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रही हैं। लगभग 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हमारी तीन टीमें रास्ते में हैं और सड़क खुलते ही वे घटनास्थल पर पहुंच जाएंगी। पंतनगर, गौचर और जोशीमठ में हमारी टीमें तैयार हैं। मौसम में सुधार होते ही उन्हें भेजा जाएगा।

**मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन बैठक की**

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ का आकलन करने के लिए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (ईओसी) में एक आपदा प्रबंधन बैठक की। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी ली। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों की अद्यतन स्थिति का भी जायजा लिया।

**उत्तरकाशी-गंगोत्री के बीच एनएच-34 राजमार्ग पर सड़कें क्षतिग्रस्त**

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अनुसार, उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के कारण उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच एनएच-34 राजमार्ग पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पापड़गाड़ में 100 मीटर का हिस्सा बह गया है और धराली के पास भारी मलबा आने से सड़क अवरुद्ध हो गई है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) लगातार हो रही बारिश और कठिन परिस्थितियों के बावजूद क्षति की मरम्मत के लिए काम कर रहा है।

# सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटरों की ईसी से मांगी डिटेल

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग (ईसी) को निर्देश दिया है कि वह बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए करीब 65 लाख मतदाताओं की पूरी जानकारी 9 अगस्त तक पेश करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जानकारी उन राजनीतिक दलों के साथ-साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नाम की एनजीओ को भी दी जाए, जिसने इस मुद्दे पर याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून को विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) शुरू किया था। इसके तहत 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें 7.24 करोड़ मतदाता दिखाए गए। लेकिन इसमें से 65 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि ये लोग या



तो मर चुके हैं, दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं, या दो जगहों पर नाम था। जस्टिस सूर्यकांत, उज्ज्वल भुयान और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा, हमें हर उस वोटर की जानकारी चाहिए जिसका नाम हटाया गया है। ये देखें कि किस आधार पर नाम हटे हैं। वहीं एनजीओ की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि, राजनीतिक पार्टियों को हटाए गए वोटरों की लिस्ट दी गई है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन मरा है, कौन शिफ्ट हुआ है,

- **बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम**
- **एक प्रति एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को देने का आदेश**
- **हम प्रभावित होने वाले हर मतदाता से संपर्क करेंगे - सुप्रीम कोर्ट**

या किसका नाम गलत तरीके से हटा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि वह 9 अगस्त तक जवाब दाखिल करे, ताकि 12-13 अगस्त को इस मामले पर पूरी सुनवाई हो सके। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मांग की है कि 65 लाख हटाए गए नामों की पूरी सूची प्रकाशित की जाए। हर नाम के साथ यह भी बताया जाए कि उसे क्यों हटाया गया, मौत, स्थायी स्थानांतरण या कोई अन्य वजह। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर कहा, हम वोटर लिस्ट को साफ करने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि अपात्र लोग हटें और केवल सही लोग वोटर लिस्ट में रहें। इसमें मौत की वजह से करीब 22.34 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए करीब 36.28 लाख मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं। वहीं जिन मतदाताओं के नाम दो जगहों पर थे उनकी संख्या करीब 7.01 लाख है। इससे पहले 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी को गंभीरता से मान्य दस्तावेज माना जाए और इनसे नाम हटाने की बजाय जोड़ने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाए।

## पीएम मोदी, ट्रंप के सामने नहीं टिक सकते.., राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला



नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि अडाणी समूह के खिलाफ अमेरिका में चल रही जांच के कारण पीएम मोदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने टिक नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस जांच से वित्तीय संबंधों का कथित खुलासा होने का खतरा है। एक्स पर साझा एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, भारत, कृपया समझें- राष्ट्रपति ट्रंप की बार-बार की धमकियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अदाणी मामले में अमेरिका की जांच चल रही है। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि, एक खतरा मोदी, एए और रूसी तेल सौदों के बीच के वित्तीय संबंधों का खुलासा होने का भी है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका भारत पर काफी बढ़ा हुआ टैरिफ लगाएगा। उन्होंने दावा किया कि रूस से खरीदे गए तेल का हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेचा जा रहा है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर साझा पोस्ट में लिखा, भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से, मैं भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी वृद्धि करूंगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!!!

## बिहार में एसआईआर को लेकर एक भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं की आपत्ति, चुनाव आयोग ने जारी कर दी सूची



नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी एसआईआर को लेकर एक भी आपत्ति का दावा नहीं किया है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में सभी राजनीतिक पार्टियों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने 1 अगस्त को बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद से 6 अगस्त (सुबह 9 बजे) तक एसआईआर को लेकर कोई आपत्ति नहीं की है। चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार, बिहार में राजद के 47,506 बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) हैं, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से एसआईआर को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के 1,496 बीएलए हैं, लेकिन किसी भी बीएलए की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि 12 राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.60 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया।

**मतदाताओं से सीधे मिले दावे और आपत्तियां**

चुनाव आयोग ने कहा कि प्रारूप सूची के संबंध में मतदाताओं से सीधे 3,659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी /सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ/एईआरओ) द्वारा 7 दिनों की समाप्ति के बाद किया जाना है। आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को, ईआरओ/एईआरओ द्वारा निष्पक्ष जांच करने और सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद स्पष्ट आदेश पारित किए बिना नहीं हटाया जा सकता।

## बिहार मतदाता विवाद : विपक्ष का संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन, चर्चा से क्यों डर रही है सरकार - प्रियंका गांधी




नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन बुधवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एआईआर) प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और बड़े पैमाने पर नाम हटाने के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सांसदों ने हाथ में बैनर लिया, जिस पर लिखा था द एसआईआर- डिमांड डिस्कशन, नॉट डेलिटेशन यानी हटाओ नहीं, चर्चा करो। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि न संसद चला पा रही है और न ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जवाब दे पा रही है।

उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ चर्चा की मांग कर रहे हैं। उनके लिए इसे सुलझाना आसान है? वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उनके हाथों में बंगाल का अपमान बंद करो जैसे संदेशों वाले पोस्टर थे। इस बीच, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में काम स्थगन नोटिस दिया ताकि इस मुद्दे पर चर्चा कराई जा सके। वहीं, लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव लाकर बिहार में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर तुरंत चर्चा की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दूसरी ओर बात अगर विधायी कार्यों की बात करें तो, लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर के बजट व्यय पर बयान देंगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक पेश करेंगे। यह दोनों विधेयक खेलों के विकास, खिलाड़ियों की भलाई और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं। इसके अलावा, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पेश करेंगे, जो भारत के समुद्री कानूनों को अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप बनाएगा और भारतीय शिपिंग उद्योग को मजबूत करेगा।

## खरगे बोले- बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर संसद में चर्चा चाहता है विपक्ष, सरकार इच्छुक नहीं



नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को कहा कि विपक्षी पार्टियां बिहार में चल रही विशेष गहनपुनरीक्षण (एसआईआर) यानी मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा पर संसद में चर्चा की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। खरगे ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से इनकार करती है, तो इसे ऐसा माना जाएगा कि वह लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानती। उन्होंने कहा, एसआईआर पर चर्चा बेहद जरूरी है ताकि हर भारतीय नागरिक के मतदान के अधिकारों की रक्षा की जा सके। विशेष गहन पुनरीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग मतदाता सूची को दोबारा जांचेगा, ताकि उसमें किसी भी तरह की गलती, दोहराव या अपात्र नामों को हटाया जा सके और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके।

**विपक्ष की क्या है चिंता?**

विपक्षी दलों का कहना है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, और इससे कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, जिससे उनके वोट देने का अधिकार छिन सकता है। इसी वजह से वे इस पर संसद में खुली बहस चाहते हैं। खरगे ने यह भी कहा कि, अगर सरकार वाकई में लोकतांत्रिक मूल्यों को मानती है, तो उसे एसआईआर पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए।

**सरकार की चुप्पी पर खरगे का सवाल**

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अनुसार, केंद्र सरकार एसआईआर पर चर्चा से बच रही है, जिससे शक पैदा होता है कि वह जानबूझकर इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है।

## सपा कर रही तुष्टिकरण, हम दे रहे संतुष्टिकरण- योगी

बरेली।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली को विकास की बड़ी सौगात दी। हजियापुर में 129 करोड़ की लागत से बने बरेली मंडल के पहले यूनानी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर जहां इलाज और पढ़ाई की राह आसान की, वहीं बरेली कॉलेज के मैदान से 22.64 हजार करोड़ रुपये की 545 परियोजनाएं जनता को समर्पित कीं। बरेली में 2017 से पहले बरेली में आए दिन बड़े दंगे होते थे। बरेली एक दंगाग्रस्त जनपद बन गया था। लेकिन आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन रही है। बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटी नाथ, बाबा वनखंडी नाथ, बाबा धोपेश्वर नाथ, बाबा तपेश्वर नाथ, बाबा मढ़ीनाथ, बाबा पशुपति नाथ मंदिर के लिए नाथ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारें बांटने का काम करती थीं। वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टिकरण पराकाष्ठा को पूर्ण करती थीं, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान दिया जाता था। मगर भाजपा की सरकार तुष्टिकरण नहीं बल्कि विकास के जरिए जनता की संतुष्टिकरण का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास कार्यों के साथ जोड़ रही है। न्यू बरेली के रूप में बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम में तमाम परियोजनाओं को पूरा करके दिखाया है। जिसके परिणाम दिख रहे हैं। अब कोई बरेली को कोई दंगा ग्रस्त नहीं कह सकता। सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा के बदनाम करने की कोशिश की गई।सीएम ने कहा जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे और षणयंत्र रचेंगे, छद्म वेष में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो सारे माहौल को खराब करते हैं। लेकिन समाज की

**सीएम योगी बोले- समाज विरोधी तत्व कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश...पुलिस की तत्परता ऐसे तत्व बेनकाब**

जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं। बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान जलाभिषेक कर अपनी सेवा को महादेव को अर्पित किया। पिछली सरकारें दंगों के साथ लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा करती थीं।

मगर डबल इंजन की भाजपा सरकार भयमुक्त वातावरण देकर विरासत और विकास को जोड़कर लोगों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बरेली में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

## बिहार में सात बीएलओ निलंबित

पटना।

बिहार में भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार को कम से कम सात बूथ लेवल अधिकारियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने और निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने से इनकार करने के आरोप में निलंबित कर दिया। पटना जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी ने बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बीएलओ के निलंबन के कारणों में उनकी ड्यूटी से अनुपस्थिति, मानक प्रक्रिया की अनदेखी, मनमाने ढंग से निर्णय लेना और वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श न करना शामिल है। मोकामा से तीन और फतुहा विधानसभा क्षेत्र से चार बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

## बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर

बीजापुर। जिले के गंगालुर थाना क्षेत्र में आज सुबह से सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक नक्सली को मार गिराया है। मौके से एक नक्सली का शव और हथियार भी बरामद किये जाने की खबर है। सूत्रों के अनुसार, मुठभेड़ गंगालुर क्षेत्र के जंगलों में हो रही है और अभी भी रुक-रुक कर फायरिंग जारी है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।

## पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद पर हमला, आरोपी बोला- सनातन को अपमानित करते हैं... इसलिए ऐसा किया

रायबरेली। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का शहर के सारस मोटल चौराहा पर स्वागत हो रहा था। इस दौरान दो युवकों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद समर्थकों ने दोनों युवकों को पीटा। पुलिस ने पिटाई करने वाले दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। सीओ सदर अमित सिंह ने कहा पकड़े गए युवकों की अभी पहचान नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज होगा। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद ने कहा कि ये करणी सेना के नाम पर



कीड़े-मकोड़े हैं। ये लोग खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बताता है कि योगी सरकार में गुंडे-माफियाओं के हौसले कितने बढ़े हुए हैं। वहीं, पुलिस की गिरफ्त में आए हमलावर ने कहा कि स्वामी लगातार सनातन का विरोध करते हैं इसलिए उन पर हमला किया। सीओ अमित मिश्रा ने बताया कि दो लोगों को पूर्व मंत्री पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। स्वामी प्रसाद लगातार विवादित टिप्पणियां करने के कारण चर्चा में रहते हैं।

## कोर्ट का अपमान बर्दाश्त नहीं - भाजपा सांसद प्रियंका के खिलाफ दायर करेंगे अवमानना याचिका

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के हाल ही में दिए गए बयानों को लेकर उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की जाएगी। मिश्रा का यह बयान तब सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर टिप्पणी की। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने उनके बचाव में जो बयान दिए हैं, वह अदालत की अवमानना के दायरे में आते हैं। मिश्रा ने कहा, उन्होंने (प्रियंका गांधी) मीडिया के सामने कई तरह के बयान देकर अदालत की अवमानना की है। इसलिए हम उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिना यह समझे कि अदालत का मकसद क्या था, गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। यह याचिका बार (वकीलों का संगठन) और वकीलों की ओर से दायर की जाएगी।

इस देश की जनता ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगी। एक दिन पहले प्रियंका गांधी



ने अपने भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बचाव किया था। यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत-चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी के बयानों को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। मंगलवार को शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी भारतीय सेना का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं।